



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर०एम०ए० नं०-०३/२०१४-१५

मुन्ना साह

बनाम

रजिन दुद्द

—: आदेश :-

दिनांक

14.12.14

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों को अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्ता मुन्ना साह, पिता-स्व० गणेश साह, सा०-किताजोर, धाना-पोड़ैयाहाट, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा के न्यायालय के आर०ई०आर० केश नं०-२३/२०१२-१३ आदेश दिनांक-२४.०१.२०१४ के विरुद्ध अपील वाद दायर किया है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा ने आर०ई०आर० केश नं०-२३/२०१२-१३ आदेश दिनांक-२४.०१.२०१४ के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम १९४९ की धारा २० एवं ४२ के तहत अपीलकर्ता को मौजा-किताजोर नं० १४८ जमाबंदी नं० ८, दाग नं० २२८ रकवा ००-०४-०० धुर जमीन से उच्छेद किया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी ने निम्न न्यायालय में मौजा-किताजोर नं० १४८ जमाबंदी नं० ८ दाग नं० २२८ रकवा ००-०४-०० धुर जमीन से उच्छेद करने के लिए आवेदन दिया था। जबकि अपीलकर्ता उक्त दाग नं० के मात्र ००-०२-०० धुर जमीन पर मकान बना कर सपरिवार निवास करते आ रहे हैं। उक्त वर्णित जमीन अपीलकर्ता के पिता को वर्ष १९३७ ई० में जमाबंदी रैयत से कुर्फा बंदोबस्ती से प्राप्त हुआ था। तब से अपीलकर्ता के पिता उस पर दखलदार थे एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अपीलकर्ता उस जमीन पर दखलदार हैं। अपीलकर्ता भूमिहीन है तथा वर्तमान में उक्त जमीन का स्वरूप भी बदल गया है। इसलिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम १९४९ की धारा २० एवं ४२ से प्रभावित नहीं होगा। माननीय उच्च न्यायालय के बी०बी०सी०जे० १९८८ पेज नं० ३७२१, जे०एल०जे०आर० २००३ भोल्यूम ३ पेज नं० २२३ के न्याय निर्णय के अनुसार भी आवास की जमीन से उच्छेद नहीं किया जा सकता है। लेकिन निम्न न्यायालय ने अपीलकर्ता को उक्त जमीन से उच्छेद का

9/2

2
आदेश पारित किया है एवं आदेश में उक्त जमीन का रकबा अंकित नहीं किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत के लिए अनुरोध किया है।

प्रक्रिया चलने के दौरान ही उत्तरवादी नारायण दुडू की मृत्यु हो गई है। उनके स्थान पर उनके पुत्र रजिन दुडू, श्रीलाल दुडू एवं राजेश दुडू को प्रतिस्थानी पक्षकार बनाया गया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी के पूर्वज से अपीलकर्ता के पूर्वज को मौजा-कित्ताजोर नं० 148 जमाबंदी नं० 8 दाग नं० 228 रकबा 00-02-00 धुर जमीन बारावास के लिए दिया था। तभी से अपीलकर्ता के पूर्वज उस पर मकान बना कर रह रहे थे एवं वर्तमान में अपीलकर्ता उस पर सपरिवार निवास कर रहे हैं। अपीलकर्ता से उत्तरवादी को कोई शिकायत या विवाद नहीं रह गया है। भूलवश उत्तरवादी ने वाद दायर किया था। उत्तरवादी को अब उक्त जमीन पर कोई दावा नहीं रह गया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक 416/रा० दिनांक 28.03.2020 से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया है कि कित्ताजोर थाना नं० 148 जमाबंदी नं० 08 दाग नं० 228 के कुल रकबा 02-08-06 धुर जमीन जमाबंदी रैयत छोटा गोपीया दुडू वल्द सुरजु दुडू कौम संताल शा० देह कहकर अंकित है। उक्त दाग नं० 228 के अंदर 00-02-00 धुर भूमि पर मुन्ना साह शा० देह पोड़ैयाहाट का दखल बना हुआ है। वर्तमान समय में किसी प्रकार का सहन नहीं है। अपीलकर्ता उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। जबकि उत्तरवादी जमाबंदी रैयत के वंशज है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा-कित्ताजोर नं० 148 जमाबंदी नं० 8 दाग नं० 228 कुल रकबा 02-08-06 धुर जमीन जमाबंदी रैयत छोटा गोपीया दुडू वल्द सुरजु दुडू के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। उक्त दाग नं० के अंदर रकबा 00-02-00 धुर जमीन अपीलकर्ता ने कुर्पा से प्राप्त करने का दावा किया है। लेकिन उन्होंने अपने दावा के अनुरूप प्रतिकूल प्रभाव से उक्त जमीन पर दखल का कोई भी साक्ष्यजनित कागजात दाखिल नहीं किया है। अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट

के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त जमीन पर अपीलकर्ता का कोई सहन नहीं है। वर्तमान अपीलवाद में उत्तरवादी की ओर से यह कहा गया है कि उसके पूर्वज के द्वारा उक्त जमीन वासोवास के लिए अपीलकर्ता के पूर्वज को दिया था। लेकिन चूँकि उक्त जमीन रैयती प्रकृति की जमीन है एवं गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा के अनुसार बाड़ी दौयम की जमीन है। जो कृषि योग्य जमीन है और संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 के धारा 20 के तहत रैयती जमीन का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड़डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0-23/2012-13 आदेश दिनांक-24.01.2014 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
गोड़डा।


उपायुक्त,
गोड़डा।

फा-219
23/12/21

Seen
mm
20/12/2021